

पुलिस कार्रवाई

दिल्ली और हिमाचल पुलिस के बीच हुए बवाल पर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिमाचल पुलिस की कार्रवाई को उचित बता रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने प्रदेश पुलिस की कार्रवाई को गैर-कानूनी करार दिया है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार की किसी भी अपराधी को बचाने की कोई मंशा नहीं है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार किसी दूसरे राज्य में कोई कार्रवाई करने से पहले उस राज्य की पुलिस को सूचित करना जरूरी होता है लेकिन दिल्ली पुलिस ने नियमों का पालन नहीं किया।

दूसरी ओर भाजपा विधायक विनोद कुमार ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सुकू सरकार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ए.आई. समिट में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से देश की छवि खराब हुई है।

ज्ञापन

प्रदेश भाजपा ने ए.आई. इम्पैक्ट समिट 2026 प्रकरण में दिल्ली पुलिस की वैधानिक कार्रवाई में हस्तक्षेप और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस तंत्र के राजनीतिक इस्तेमाल से उत्पन्न गम्भीर संवैधानिक संकट के संबंध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में भाजपा द्वारा लोकभवन शिमला में राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में केन्द्र सरकार के माध्यम से इस घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि ए.आई. इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन से देश की छवि धूमिल हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के इस राष्ट्रविरोधी कृत्य के संबंध में दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज हुई और दिल्ली पुलिस ने इस मामले की विधिसम्मत कार्रवाई प्रारम्भ की। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार ने अगर राजनीतिक कारणों से पुलिस तंत्र का उपयोग किया है तो ये संविधान की शपथ का उल्लंघन है।

जगत नेगी

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने हिमाचल और दिल्ली पुलिस प्रकरण को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। नाहन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल की हर मामले पर टिप्पणी करना पुरानी आदत बन गई है। जगत सिंह नेगी ने हिमाचल पुलिस की कार्रवाई को उचित ठहराते हुए कहा कि बिना वर्दी और स्थानीय पुलिस को सूचित किए बगैर लोगों को उठाना जायज नहीं है।

रोहित ठाकुर

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि भौगोलिक कठिनाईयों और प्राकृतिक आपदा जैसी चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार दूर-दराज क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण व प्रभावी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित कर रही है। ये बात आज उन्होंने शिमला में समग्र शिक्षा के तहत आयोजित यूनेस्को एच.पी. फ्यूचर्ज परियोजना की संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 में शुरू की गई एच.पी. फ्यूचर्ज परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य समावेशी भविष्य के लिए तैयार और जलवायु संवेदनशील पी.एम.श्री व अन्य विद्यालयों का विकास करना है।
